अगस्त 2024
वर्ष 38 संख्या 8
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

केंद्रीय बजट 2024–25 पर

चुनावों में उठे मुद्दों पर दिखावा तथा कारपोरेट और अभिजात तबकों को लाभ

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई वर्ष 2024–25 के लिए संसद में पूर्ण बजट पेश किया है। (अंतरिम बजट लोकसभा चुनावों से पहले पेश किया गया था) इस बजट में मोदी सरकार की आर्थिक नीति को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि हाल में संपन्न हुए चुनावों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, उन पर कुछ दिखावा किया गया है, जिनके चलते किसानों और ग्रामीण गरीबों के बढ़ते गुस्से के बीच भाजपा अल्पमत में आ गई थी। इस बार मोदी सरकार सहयोगी दलों खासकर तेलुगू देशम और जनता दल (यू) पार्टी की बैसाखी पर है और यह भी केंद्रीय बजट में परिलक्षित हुआ है। हालांकि यह सब मोदी सरकार की कॉरपोरेट समर्थक आर्थिक नीतियों के ढांचे के भीतर हुआ है। हिंदुत्व ब्रांड के साथ इसे "विकास भी, विरासत भी" के नारे के साथ मिलाया गया है, जिसमें पहले नारे से लोगों को गुमराह किया गया और दूसरे से इतिहास और परंपराओं को विकृत किया गया है। ऊपर वर्णित परिवर्तनों को शामिल करते हुए इस बजट में अंतरिम बजट का अनुसरण किया गया है, जिसमें व्यय में लगभग 1% की वृद्धि की गई है। अंतरिम बजट की तरह ही गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए दिखावटी चिंता व्यक्त की गई, लेकिन बजट आवंटन में इसे नजरअंदाज किया गया है।

केंद्र सरकार मजबूत आर्थिक विकास का दावा कर रही है, लेकिन आंकड़ों में हेराफेरी और फर्जी आंकड़ों के कारण यह दावा संदिग्ध है, जबकि भारत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया के गरीब देशों में से एक बना हुआ है। इसके अलावा इसे बढ़ती असमानता, अरबपतियों की बढ़ती संख्या और बढ़ती गरीबी, अभाव और बेरोजगारी की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गणना (अनुमानित 7.5%) नाम मात्र वृद्धि को मुख्य (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) मुद्रास्फीति में समायोजित करके की जाती है, जो कि 3.01% है और जो स्पष्ट रूप से खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और ईंधन की उच्च कीमतों को गणना से बाहर रखने के साथ वास्तविक मुद्रास्फीति से बहुत कम है। यह वृद्धि एक रोजगार हीन वृद्धि है, जिसका लाभ केवल कॉरपोरेट और अत्यंत अमीर तबके को ही मिल रहा है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था के जोरदार लेकिन काफी हद तक खोखले दावों के बावजूद सरकार लोगों की दयनीय स्थिति और अर्थव्यवस्था की संकटग्रस्त प्रकृति को नहीं छुपा सकती। सरकार की 27% से अधिक प्राप्तियां उधार के रूप में प्राप्त होती हैं और लगभग एक चौथाई सरकारी व्यय ब्याज भुगतान में चला जाता है। जैसा की आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि कॉरपोरेट मुनाफे में तैर रहे हैं, लेकिन निजी निवेश गिर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से विरोधाभासी स्थिति शासक वर्गों के चरित्र, साम्राज्यवाद के प्रति उनकी अधीनता को दर्शाती है। वास्तव में सरकार कॉरपोरेट को सार्वजनिक धन (राज्य निधि) उपलब्ध कराते हुए साम्राज्यवादी देशों से पूंजी मांग रही है। यह सतत विकास के मिथक को उजागर करता है।

वित्त मंत्री ने विदेशी फर्मों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 40% से 35% की कटौती की घोषणा की है और यह भी घोषणा की है कि एफडीआई को नियंत्रित करने वाले नियमों को सरल बनाया जाएगा। सरकार ने 'एंजेल टैक्स' को वापस लेने की घोषणा की है, जो 2012 से उन फर्मों पर लगाया गया था, जिनमें विदेशी निवेश वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक था। फोर लेबर कोड को लागू करने के प्रयासों के साथ इन सभी उपायों का उद्देश्य साम्राज्यवादी देशों से पूंजी को आमंत्रित करना है। इस उम्मीद में कि वे चीन के साथ बढ़ते अंतर विरोधों के बीच भारत को निवेश के लिए चुनेंगे। विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाकर कॉरपोरेट की सेवा करना भी लक्ष्य है। लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि वाले जीएसटी संग्रह का उपयोग उत्पादन बढ़ाने या पीड़ित लोगों को राहत देने में निवेश करने के बजाय राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया गया है। जबकि विदेशी निवेश आकर्षित करने और कॉरपोरेट को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने जीएसटी को सरकार के पूंजीगत व्यय में शामिल करके इसे और आगे बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि बड़े पूंजीपति सीधे राज्य के निवेश से मुनाफा निकलेंगे। यह स्थिति भारतीय कॉरपोरेट (बड़े पूंजीपतियों) के दलाल और नौकरशाही चरित्र को सामने लाती है। वित्त मंत्री ने सीएसआर फंड का इस्तेमाल अपने प्रशिक्षुओं को भुगतान करने के लिए अनुमति दी है, जो उनकी फर्मों में काम करेंगे। इस तरह उन्हें समाज के प्रति किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च पर बहुत जोर दिया गया है। यह ज्यादातर पीपीपी मोड में किया जाता है, जिससे कॉरपोरेट और बड़ी निर्माण फर्मों को सरकारी खर्चे से अत्यधिक और गारंटीकृत लाभ कमाने में मदद मिलती है। उद्योगों और कृषि की उपेक्षा करने वाली यह एकतरफा नीति व्यवहार्य नहीं है, जबकि सरकार एफडीआई का इंतजार कर रही है। इस क्षेत्र में अधिकांश नौकरियां संविदात्मक, कम वेतन वाली और बिना किसी सुरक्षा प्रावधान के हैं।

हाल के दिनों में लोगों की चिंताओं को छिपाने की कोशिश की जा रही है। कृषि संकट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि वह पहले से ही उचित एमएसपी दे रही है, जबकि किसानों की स्वामीनाथन समिति की सिफारिश के अनुसार सी 2+ 50% एमएसपी की मांग को दरकिनार कर दिया गया है। किसानों के बढ़ते कर्ज का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। कृषि में गहराते संकट को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए आवंटन में कोई वृद्धि की गई है। मनरेगा आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि यह पिछले वर्ष खर्च की गई राशि से भी कम है। यह खर्च ग्रामीण संकट और ग्रामीण गरीबों के गुस्से पर निर्भर करता है। दूसरी ओर सरकार की मंशा को दर्शाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण को आसान बनाया जाएगा। इससे लोगों और पर्यावरण पर और हमले होने तय हैं। उर्वरक सब्सिडी में कटौती, किसानों के बोझ को बढ़ाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिससे साम्राज्यवादी देशों को इस उपज का निर्यात संभव हो सके।

वित्त मंत्री ने बेरोजगारी की समस्या को इस बजट का मुख्य बिंदु बनाने की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एससी और एसटी के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर

1 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सात सदस्यीय संविधान पीठ के बहुमत के फैसले के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उप–वर्गीकरण को वैध ठहराया है। यह माना गया कि उप–वर्गीकरण उनके बीच अधिक पिछड़े और उत्पीड़ित वर्गों को कवर करने के उद्देश्य से वैध है ताकि उन्हें भी अधिकार उपलब्ध कराए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया है, जहां कोर्ट ने इस तरह के उप–वर्गीकरण को असंवैधानिक ठहराया था।

हालांकि एससी और एसटी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले सभी सामाजिक समूह पिछड़ेपन में एक समान नहीं हैं, हालांकि वे प्रमुख सामाजिक समूहों, उच्च जातियों के संबंध में समान रूप से पिछड़े और उत्पीड़ित हैं। इसलिए, न्यायपालिका को सावधानी बरतनी चाहिए कि इन वर्गों के अधिक पिछड़े और उत्पीड़ित लोगों तक पहुंचने के नाम पर उत्पीड़न और भेदभाव को कायम न रखा जाए।

इसलिए, नौकरियों, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के लाभों को सब तक पहुंचने के उद्देश्य से, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि जबकि उप–कोटा उस उप–वर्गीकरण के तहत समूहों को कुछ अधिकार देने के लिए है, यदि ये उन समूहों से नहीं भरे जाते हैं तो ये उप–कोटा सामान्य श्रेणी में नहीं जाएंगे, बल्कि उसी श्रेणी के तहत अन्य उप–कोटा से यानी एससी या एसटी से ही भरे जाएंगे। यह इस संभावना को विफल करने के लिए आवश्यक है कि इस उप–वर्गीकरण का उपयोग संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाए, बल्कि इसका उपयोग केवल एससी और एसटी के अधिक पिछड़े वर्गों को उपलब्ध कराने के घोषित लक्ष्य के लिए ही किया जाए।

उक्त पीठ के चार सदस्यों ने सरकार से इस बारे में सिफारिश की है कि वह एस.सी. व एस.टी. की 'मलाईदार' परत को आरक्षण से बाहर रखने के लिए नीति बनाये यद्यपि यह मुद्दा पीठ के सामने नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की कोई चर्चा ही नहीं की कि एस.सी. और एस.टी. के लिए आरक्षित स्थानों को भरा ही नहीं जाता विशेषकर उच्च स्थानों पर तथा उच्च संस्थानों में। इन स्थानों पर एस.सी. व एस.टी. का प्रतिशत चीख चीखकर इस बात की पुष्टि करता है। इस बात को नजरंदाज करना सामाजिक न्याय के बारे में संविधान द्वारा घोषित लक्ष्य तथा प्रावधानों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता को संदेह के दायरे में खड़ा कर देता है।

सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में इन सभी समूहों के बीच अधिक एकता बनाने के लिए उप–वर्गीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इसका उपयोग वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में सभी आर्थिक रूप से शोषित और सामाजिक रूप से उत्पीड़ितों के बीच अधिक एकता के लिए किया जाना चाहिए।

(सीपीआई (एम-एल)-न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 1 अगस्त 2024 को जारी)

केन्द्रीय बजट 2024-25 पर इफ्टू का बयान

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को वर्ष 2024–25 के लिए इस एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया है। बजट से स्पष्ट है कि मोदी की एनडीए सरकार पिछली दो मोदी सरकारों की मजदूर विरोधी कॉरपोरेट परस्त नीति को पूरी तरह से जारी रखने जा रही है जबकि भारत का मजदूर वर्ग मूल्य वृद्धि, अस्थायी व कम वेतन वाली नौकरियों और बेरोजगारी के बोझ तले दबा है। बजट ने कॉरपोरेट को प्रत्यक्ष कर राहत और सभी प्रकार के समर्थन की पेशकश की है, वह भी बेरोजगारी से निपटने के नाम पर!

बजट में विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों को सरल बनाया जाएगा। 2012 से स्टार्ट अप पर लगाया जाने वाला एंजेल टैक्स वापस ले लिया गया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्र सरकार साम्राज्यवादी पूंजी को आमंत्रित करने के लिए लाल कालीन बिछाना चाहती है। यह सब एनडीए सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद की पहली घोषणा, 100 दिनों के भीतर अर्थात सितंबर 2024 के अंत तक मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड को लागू करने के साथ जुड़ा हुआ है। ये कोड भारत के मजदूरों के शोषण को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कॉरपोरेट की मांगों को पूरा करती हैं।

2014 से 2024 के बीच कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण कॉरपोरेट टैक्स से राजस्व 4.28 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन आयकर से कर राजस्व 2.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है, यानी आयकर से राजस्व कॉरपोरेट कर से राजस्व से अधिक हो गया ! इसी अवधि में सकल कर राजस्व (जीटीआर) में कॉरपोरेट टेक्स का प्रतिशत 34.5 से घटकर 26.6 प्रतिशत हो गया, जबकि जीटीआर के प्रतिशत के रूप में, आयकर से राजस्व 20.8 से बढ़कर 30. 9 प्रतिशत हो गया है। माना जा रहा था कि 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में रियायत से निवेश और नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन इससे केवल राजस्व का नुकसान हुआ। कोई नौकरियां पैदा नहीं हुईं।

कॉरपोरेट के लिए सार्वजनिक धन से अधिक सहायता युवाओं को लुभाने के उद्देश्य से की गई बड़ी घोषणा में छिपी हुई है। 21 वर्ष से 24 वर्ष की आयु के बीच के 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 वर्षों में 500 बड़ी कंपनियों में एक वर्ष के लिए प्रशिक्षु के रूप में रखा जाएगा। उन्हें 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये एकमुश्त नकद भुगतान किया जाएगा। कंपनियां प्रशिक्षण के लिए भुगतान करेंगी और इस वेतन का 10 प्रतिशत सीएसआर फंड के माध्यम से देंगी। यह कॉरपोरेट के लिए क्या बढ़िया उपहार है ! कौन नहीं जानता कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े व्यावसायिक घरानों की कंपनियों में प्रशिक्षुओं को बाकी कार्यबल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कराकर प्रशिक्षित किया जाता है या निम्न दर्जे के काम में धकेल दिया जाता है ? और देश के किसी भी राज्य में तय न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन पर एक वर्ष के मजदूर, और यह वेतन भी सार्वजनिक धन और सीएसआर फंड (जो सामुदायिक कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए) से भुगतान किया जाना है ।

यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अप्रेंटिस एक्ट को कमजोर कर दिया गया था और कोई भी कंपनी निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है। उन युवा मजदूरों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है, जो बेरोजगार हैं और केवल इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ तीस से कम उम्र में सड़कों पर हैं। स्किल इंडिया भी समान परिणाम देता है, लेकिन कम से कम मजदूरों की मुफ्त आपूर्ति नहीं करता है। स्पष्ट है कि यह सार्वजनिक लागत पर एक करोड़ युवा मजदूरों को आधुनिक गुलाम के रूप में शोषण के लिए 500 बड़े व्यापारिक घरानों को आपूर्ति करने की योजना है।

पिछले वर्षों में, बुनियादी ढांचे पर (ज्यादातर पीपीपी मोड में) सरकारी खर्च पर जोर दिया गया है। यह कॉर्पोरेट और बड़ी निर्माण कंपनियों को सरकारी खर्चे से बड़े पैमाने पर गारंटीकृत लाभ कमाने देता है। इस क्षेत्र में अधिकांश नौकरियां ठेकेदारी में, कम वेतन वाली और बिना किसी सुरक्षा प्रावधान वाली हैं।

ईएलआई योजनाएं

वित्त मंत्री ने ईपीएफओ (प्रोविडेंट फंड) से संबंधित 3 ईएलआई (रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन) योजनाएं पेश की हैं और दावा किया है कि यह नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार का प्रयास है। प्रोत्साहन वास्तव में नियोक्ताओं और ईपीएफओ के लिए है। योजनाएं केवल दो वर्ष के लिए हैं। ये योजनाएं औपचारिक नौकरियों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों, विनिर्माण क्षेत्र में मजदूरों और अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए हैं। एक योजना में जो औपचारिक क्षेत्र में पहली बार काम करने वालों के लिए है, सरकार औपचारिक क्षेत्र की नौकरी में नए प्रवेश कर्ता को एक महीने का वेतन तीन किश्तों में देगी, जो अधिकतम रु. 15000 होगा और न्यूनतम एक वर्ष की नौकरी होगी। वेतन पात्रता एक लाख प्रतिमाह तक है। यदि नौकरी पहले वर्ष में समाप्त हो जाती है, तो नियोक्ता द्वारा सब्सिडी वापस कर दी जाएगी। दूसरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरियों के लिए है। इसमें सरकार उन मालिकों को सब्सिडी देगी जो 3 साल के लिए ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं और जो एक नए कर्मचारी को रोजगार देते हैं, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को ईपीएफ भुगतान के माध्यम से 4 साल के लिए 8–24 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तीसरी योजना में जो सभी क्षेत्रों पर लागू है, सरकार द्वारा प्रति माह एक लाख तक वेतन पाने वाले प्रत्येक नए कर्मचारी के ईपीएफओ में योगदान के लिए दो साल तक प्रति माह 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्ट रूप श्रम कें औपचारिकीकरण का प्रयास है, ताकि सरकार इस आधार पर बेरोजगारी में कमी का दावा कर सके। इसके लिए नियोक्ताओं को कर्मचारियों का पीएफ जमा करने में पड़ने वाले बोझ के लिए सार्वजनिक कोष से पैसा देने की पेशकश की जा रही है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र, पीएसयू और बड़ी कंपनियों के स्थायी कर्मचारियों को आयकर में बड़ी राहत का दावा किया है, लेकिन कट ऑफ 3 लाख प्रति वर्ष बनी हुई है और कुछ स्लैब बनाकर कर्मचारियों पर लागू आयकर दरों में बदलाव भी मामूली है।

एमएसएमई (माध्यम, लघु, कुटीर उद्योग) औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा प्रदाता है और जीएसटी, नोट बंदी और लॉक डाउन की तीन बड़ी मार के बाद गहरे संकट में है। उन्हें कॉरपोरेट से बचाने की जरूरत है, खासकर बाजारों के संबंध में। लेकिन बजट ने केवल उन्हें और अधिक कर्ज की पेशकश की है!

इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी मजदूर वर्ग से इस कॉरपोरेट समर्थक मजदूर विरोधी बजट के खिलाफ लामबंद होने का आह्वान करती है। 4 लेबर कोड को निरस्त करने की मांग को लेकर संघर्ष तेज करें। लेबर कोड लागू करने के लिए नियम बनाने के खिलाफ राज्य सरकारों को मजबूर करने और विपक्षी शासक वर्ग दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों पर 4 लेबर कोड को निरस्त करने की मांग करने और दबाव बनाने के लिए राज्यों में संघर्ष का निर्माण करें।

(इंडियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स (इफ्टू) की राष्ट्रीय कमेटी की ओर से अध्यक्ष अपर्णा तथा महासचिव टी. श्रीनिवास द्वारा 26.7.2024 को जारी बयान का संक्षिप्त अनुवाद)

केंद्रीय बजट 2024-25 पर

(पृष्ठ 1 का शेष)

कोशिश की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार श्रम शक्ति में नए श्रमिकों को शामिल करने के लिए हर साल 78.5 लाख नौकरियां पैदा की जानी हैं, लेकिन सरकार ने भारतीय लोगों की इस बड़ी समस्याओं में से एक के साथ धोखा किया है। एक योजना के तहत सरकार औपचारिक क्षेत्र की नौकरी में नए श्रमिकों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन देगी, जो अधिकतम रु 15000 और न्यूनतम 1 साल की नौकरी होगी। सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन युवाओं को सरकार से सिर्फ एक महीने का वेतन और 1 साल की नौकरी मिलेगी ! इसके अलावा सरकार उन मालिकों को भविष्य निधि के संबंध में सब्सिडी देगी, जो नये रोजगार देंगे। सरकार ईपीएफओ में पहले 2 साल के अंशदान का भुगतान करेगी, जो लगभग 72000 है। पूरा जोर औपचारीकरण पर है। ताकि सरकार इस आधार पर बेरोजगारी में कमी का दावा कर सके। कर्मचारियों पर लागू आयकर दरों में भी मामूली बदलाव किया गया है।

वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में 500 बड़ी कंपनियों में एक करोड़ प्रशिक्षुओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्हें वजीफा के रूप में रु 5000 प्रतिमाह दिए जाएंगे, जो न्यूनतम वेतन से बहुत कम है। यह कुछ और नहीं बल्कि कॉरपोरेट को बेहद सस्ता श्रम उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि कॉरपोरेट उन्हें सीएसआर फंड से भुगतान कर रहे हैं। ये तथाकथित प्रशिक्षु कॉरपोरेट क्षेत्र में नियमित नौकरियों पर दबाव डालेंगे, जबकि संबंधित कंपनी द्वारा प्रशिक्षुओं को नौकरी में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट में बात युवाओं की की है, लेकिन सेवा की है कारपोरेट की।

वित्तमंत्री ने एमएसएमई की मदद करने के बारे में बहुत शोर मचाया, लेकिन जो कुछ भी बजट में पेश किया गया वह सिर्फ कर्ज था। सरकार या तो असमर्थ है या फिर इस क्षेत्र में संकट के पीछे के वास्तविक कारणों की पहचान करने को तैयार नहीं है, जो औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। एमएसएमई को कॉरपोरेट से बचने की जरूरत है खासकर बाजार के मामले में।

आरएसएस–बीजेपी सरकार ने जीएसटी के जरिए राज्य की राजकोषीय शक्तियों को कमजोर कर दिया है। राज्यों को आवंटन केंद्र द्वारा तय किया जाता है और यह आवंटन कम होता जा रहा है। वित्तीय लाभ राज्य सरकारों के लिए लंबित रखे जाते हैं। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को अधिक आवंटन किया गया है, क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार इन राज्यों में सत्तारूढ़ दलों पर निर्भर है। 15000 करोड रुपए आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए आवंटित किए गए हैं और आने वाले समय में और भी दिया जाऐगा, जबकि बिहार को राजमार्ग, हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज देने का वायदा किया गया है। यहां इन आवंटनों का सवाल नहीं है बल्कि यह है कि इन्हें अधिकार के रूप में नहीं बल्कि उपकार के रूप में पेश किया जा रहा है। पूर्वोदय यानी पूर्वी राज्यों का विकास काफी हद तक एनडीए शासित राज्यों तक सीमित रहेगा और ज्यादातर बुनियादी ढांचे से संबंधित होगा, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन को काफी हद तक अंतरिम बजट के स्तर पर बनाए रखा गया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए। खाद्य और ईंधन की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। सरकार पेट्रोल या डीजल पर कर को कम से कम जीएसटी के उच्चतम स्लैब के स्तर तक काम करने की मांगों को हठ पूर्वक खारिज कर रही है, जिससे उनकी कीमतें काफी कम हो जातीं और आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों पर इससे काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

वर्ष 2024–25 के लिए केंद्रीय बजट में लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है, बल्कि यह उन पर बोझ बढ़ाता है। यह आरएसएस–बीजेपी सरकार द्वारा मेहनतकशों, मजदूरों और किसानों के खिलाफ हमले की निरंतरता है। सीपीआई (एमएल)– न्यू डेमोक्रेसी इन बजट प्रस्तावों को पूरी तरह से खारिज करती है।

सीपीआई (एमएल)– न्यू डेमोक्रेसी सभी कार्यकर्ताओं से इस जन विरोधी बजट के खिलाफ लोगों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान करती है।

(सीपीआई (एमएल)- न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति द्वारा 18 जुलाई को जारी बयान)

क्या छोटा सा गाजा 'शक्तिशाली' इजराइल का कब्रिस्तान बनेगा?

पी. प्रसाद

इतिहास गवाह है आक्रमणकारियों और उत्पीड़ित राष्ट्रों को अधीन करने वाली शक्तियों को जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ता है और लोग उन्हें अंततः हरा देते हैं, चाहे वह रोमन और ग्रीक साम्राज्य हो या आधुनिक विश्व की महाशक्तियाँ। यह वियतनाम, कोरिया और हाल ही में इराक, अफगानिस्तान में साबित हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस, नाजी जर्मनी, फासीवादी इटली, अमेरिका, समाजिक साम्राज्यवादी यूएसएसआर आदि के लिए ये कड़वे सबक हैं। तथाकथित आधुनिक हथियारों से सुसज्जित शासन, जिसमें परमाणु राज्य भी शामिल हैं, कब्जे वाली भूमि के लोगों के प्रतिरोध का सामना नहीं कर सकते। जैसा कि माओ ने कहा था, तथाकथित अजेय साम्राज्यवादी शासन और आक्रमणकारी 'कागजी शेर' हैं। यह इतिहास का नियम है और कोई भी महाशक्ति इस नियम से ऊपर नहीं है। यह अब एक बार फिर से बहुत छोटे गाजा में साबित हो रहा है। वास्तव में, वर्तमान छोटा गाजा सभी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्विरोधों के बढ़ने का केंद्र बन गया है।

जब हमस ने 7 अक्तूबर 2023 को इसराइल पर सशस्त्र हमला किया, तो पश्चिमी शक्तियों और अधिनायकवादी शासन और उनके नेता, बाइडेन से लेकर मोदी तक ने इस हमले की घोर निंदा सबसे बर्बर कृत्य के रूप में की और छोटे गाजा पर जायोनी इसराइल के हमलों का आत्मरक्षा में की गई कार्यवाही का समर्थन किया।

फिलिस्तीनी लोगों के मुक्ति संघर्ष के लंबे समय से समर्थक रहे साम्राज्यवाद विरोधी राजनीतिक दलों और ताकतों के बीच मिश्रित राय व्यक्त की गई हैं। उन्होंने गाजा के खिलाफ जायोनी इसराइल की आक्रामकता का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हमस के हमले की निंदा नहीं की। लेकिन उनमें से कुछ की राय थी कि हमस का हमला सही कार्रवाई नहीं हो सकता और फिलिस्तीनी लोगों की दीर्घकालिक मुक्ति के लिए किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। वास्तव में, अधिकांश समाजवादी लोकतांत्रिक दलों और अधिकांश प्रगतिशील वामपंथी बुद्धिजीवी उस समय गाजा की जमीनी हकीकत का सही मूल्यांकन नहीं कर सके।

बहुत ही कम साम्राज्यवाद विरोधी ताकतें, मुख्य रूप से अरब देशों से और कुछ मार्क्सवादी लेनिनवादी दल, गाजा की जमीनी हकीकत का सही मूल्यांकन कर सके। केवल इन ताकतों ने समझा कि यह कार्रवाई फिलिस्तीनियों के लंबे मुक्ति संघर्ष में उत्प्रेरक का काम करेगी, हालांकि इसका तात्कालिक परिणाम गाजा में रक्तपात का कारण बनेगा। उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से भविष्यवाणी की थी कि गाजा अंततः जीतेगा। वास्तव में गाजा में 23 लाख लोग अपने देश की आजादी के संघर्ष में प्राण त्यागने को भी तैयार हैं।

औपचारिक मार्क्सवाद और असली मार्क्सवाद में अंतर होता है। कई मार्क्सवादी बुद्धिजीवी भी इस पहलू का सही मूल्यांकन करने में विफल रहे। इसलिए, उन्होंने हमस के कदम को गलत बताया। उन्होंने इसे एक अनावश्यक कदम माना और भविष्यवाणी की कि यह निश्चित रूप से विफल होगा। कुछ ने इसे बचकाना कार्य माना। कुछ ने इसे बहुत अपरिपक्व और रोमांचक कार्य माना। लेकिन वास्तव में, हमस का कदम केवल हमस का नहीं था। यह न केवल फिलिस्तीनी लोगों की इच्छाओं के अनुसार बल्कि उनकी मानसिक तैयारी के अनुसार भी किया गया था। वास्तव में, यह कदम केवल गाजा के लोगों के अनुसार नहीं था, बल्कि यह पश्चिमी तट और यरुशलम के लोगों की इच्छाओं और उनकी पूर्ण और मजबूत एकजुटता को भी दर्शाता है। एक वाक्य में, यह दुनिया में कहीं भी रहने वाले पूरे फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं, भावनाओं और तैयारी को दर्शाता है।

हमस की विचारधारा हमें स्वीकार्य नहीं हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी और जायोनीवाद विरोधी संघर्ष में फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें समय और स्थान को ध्यान में रखना चाहिए। जहां औद्योगिक विकास नहीं है, जहां श्रमिक वर्ग एक संगठित शक्ति नहीं है, हम उन संघर्षों को अनुचित नहीं ठहरा सकते। हमें कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति के संबंध में स्टालिन की राय को ध्यान में रखना चाहिए। हमें अफगानिस्तान जैसे बहुत पिछड़े देश के बारे में एंगेल्स की राय को ध्यान में रखना चाहिए, जिसे महान साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा गया था। इससे क्या सीखा जाना चाहिए? सही सर्वहारा संगठन या सही विचारधारा हवा या आसमान से नहीं आ सकते। इसलिए, मार्क्सवादियों को वहां की स्थिति का अपने वैचारिक दृष्टिकोण से अनुमान लगाना चाहिए, लेकिन वहां के लोगों के मुक्ति संघर्ष को आगे बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए। मार्क्सवादी लेनिनवादी ताकतों को वहां और उस समय की जमीनी हकीकत के अनुसार विश्लेषण करना चाहिए। तब वे हमस द्वारा चुने गए ठोस समय और ठोस कार्रवाई की उपयुक्तता के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

फिलिस्तीनी मुद्दा 1947 से सुर्खियों में रहा है। चार अरब–इसराइल युद्ध हो चुके हैं। तथाकथित मैड्रिड सम्मेलन, ओस्लो समझौता–I, ओस्लो समझौता–II, कैंप डेविड समझौता आदि 1992 के बाद हुए। ये सभी युद्ध और संधियाँ अरब शासकों की मदद से हुईं। फिलिस्तीनी लोग और उनकी राजनीतिक ताकतें मुख्य रूप से अरब सरकारों पर निर्भर थीं, जो बदले में साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन हैं। इनमें से कई सरकारें अमेरिका की कठपुतली हैं। बार–बार फिलिस्तीनी लोगों को इन कठपुतलियों द्वारा धोखा दिया गया। पहली बार गाजा के लोगों ने अपने भविष्य के रास्ते को अपने हाथों में लेने का निर्णय हमस के माध्यम से किया, जो उनका निर्वाचित निकाय है। यह फिलिस्तीनी लोगों के मुक्ति संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसलिए, 7 अक्टूबर का हमला एक अलग घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसने वास्तव में उनके मुक्ति संघर्ष के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। इसे उनकी लंबी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना और एक मील का पत्थर माना जाना चाहिए।

जो लोग इस लंबे विकास प्रक्रिया को सही ढंग से पहचान नहीं सके, उनके मन में यह राय है कि 7 अक्टूबर को हमस द्वारा उठाया गया कदम जायोनी शासन के साथ गाजा की वर्तमान दयनीय स्थिति के कारणों में से एक है। लेकिन जायोनी शासन के नौ महीने के लंबे आक्रमण के बाद, जिसमें साढ़े तीन लाख सेना शामिल है, आइए वास्तविक तथ्यों को समझें।

क्या 7 अक्टूबर का हमला हमस द्वारा एकतरफा, बचकाना और जल्दबाजी में किया गया कार्य था? अगर ऐसा होता, तो गाजा के घायल लोग हमस के खिलाफ विद्रोह कर देते। इस 9 महीने की अवधि के दौरान हमस के खिलाफ कोई विरोध नहीं हुआ। यहां तक कि 38 हजार लोगों की मौत और लगभग एक लाख लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी, गाजा के घायल लोगों से एक भी विरोध नहीं हुआ। इसके बजाय, वे वापस लड़ने के लिए अधिक दृढ़ हैं। यहां तक कि रफा के लोग, जो अब एक कब्रिस्तान की तरह दिखता है, जहां बर्बर इसराइली सेना दैनिक आधार पर हमले और घर–घर तलाशी अभियान चला रही है, वे भी वापस लड़ने के लिए दृढ़ हैं। तथाकथित अजेय शक्तिशाली इसराइल सेना अब गाजा में सामान्यतः और विशेष रूप से रफा में अपने घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है। यह लोगों के प्रतिरोध के कारण है।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गाजा के वीर लोग मृत्यु का सामना कर रहे हैं और अब भी अपने राष्ट्रीय संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा, उन्हें दुनिया भर से मजबूत एकजुटता मिल रही है। वास्तव में, उन्होंने दुनिया के लगभग 150 देशों सहित सभी कोनों से समर्थन प्राप्त कर राजनीतिक और नैतिक जीत पहले ही हासिल कर ली है। लेकिन अब वे सैनिक क्षेत्र में भी तेजी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव में, 7 अक्टूबर तक, उनकी मुक्ति का लक्ष्य एक सपना था, अब यह वास्तविकता बन रहा है।

माओ ने कहा, "एक अकेली चिंगारी घास के मैदान में आग लगा सकती है"। वर्तमान स्थिति माओ के उद्धरण का एक उदाहरण है। गाजा, 365 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाला एक छोटा सा क्षेत्र, अब पश्चिमी साम्राज्यवादी दुनिया को अभूतपूर्व स्तर पर हिला रहा है। यह लंबे समय से चली आ रही विश्व व्यवस्था को भी हिला रहा है। यह पश्चिमी साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी ताकतों के विरोध का एक केंद्र बन रहा है। एक ओर और साम्राज्यवाद विरोधी, अधिनायकवाद विरोधी प्रतिरोध बलों के लिए दूसरी ओर अपने लक्ष्यों और उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक केंद्र बन रहा है। अधिकांश साम्राज्यवादी शक्तियाँ इसराइल का समर्थन कर रही हैं, लेकिन व्यर्थ। इसके अलावा, इसराइल खुद नौ महीने से गाजा में नरसंहार करने के बाद एक मृत्यु जाल में फंसता जा रहा है। वास्तव में, गाजा अब जायोनी शासन को एक मृत्यु जाल में खींच रहा है। एक धारणा यह है कि गाजा एक मृत्यु जाल में फंस रहा है। वास्तविकता यह है कि इसराइल भी एक मृत्यु जाल में धकेला जा रहा है। अब इसराइल अपने पतन को रोकने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रहा है।

इसराइल जो एक शक्तिशाली क्षेत्रीय परमाणु महाशक्ति था, बहुत तेजी से इस दौरान कमजोर हुआ है। लेकिन इसे अब अभूतपूर्व दर से कमजोर किया जा रहा है। शक्तिशाली इसराइल, जिसकी एक शक्तिशाली सेना (आईडीएफ) है, जायोनी एजेंडा के अनुसार युद्ध को बनाए नहीं रख सकता। आईडीएफ खुले तौर पर गाजा पर युद्ध जारी रखने का विरोध कर रही है। सरकार और सेना में दरार है। यह एक साधारण बात नहीं है, बल्कि गहरे संकट का संकेत है और साथ ही शासक वर्गों में भी गहरा विभाजन है। इसराइल अपने लक्ष्यों को अपने सैनिकों के शवों और दुनिया में विश्वसनीयता की हानि के साथ लंबे युद्ध के माध्यम से हासिल नहीं कर सका, इसके बजाय, अब यह एक अकल्पनीय स्तर पर हार रहा है और कमजोर हो रहा है। अत्यधिक खर्च बढ़ाने के बाद भी इसराइल अपने सामरिक लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाया है बल्कि सैनिकों की मौत के चलते अपनी विश्वनीयता भी खो रहा है और कल्पना के परे कमजोर हो रहा है।

इस युद्ध के दौरान हाल ही में आईडीएफ (इजराइल डिफेंस फोर्स) को भारी जान माल का नुकसान हुआ है और उसने अपनी बड़ी संख्या में सैनिकों को खोया है। सैकड़ों लोग मृतकों की सूची में हैं और हजारों घायल हैं। कुछ दिन पहले, एक गोपनीय समाचार रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या हजारों तक पहुँच गई है। यह सेना के लिए एक बड़ा झटका है। यह सेना और सरकार के बीच गहराती दरार को दर्शाता है ।

1948, 1956, 1967 और 1973 के सभी अरब–इजराइल युद्धों में, इजराइली सेना विजयी रही और खुद को अजेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। लेकिन 2006 में दक्षिणी लेबनान में उसके हस्तक्षेप ने पहली बार यह साबित कर दिया कि आईडीएफ अब अजेय नहीं है। वास्तव में, तब आईडीएफ ने अपनी विश्वसनीयता खो दी थी। अब न केवल उसकी विश्वसनीयता, बल्कि सेना को जान माल का नुकसान भी हो रहा है ।

दो घोषित लक्ष्यों के साथ जब इजराइल ने गाजा पर युद्ध छेड़ा, तो उनमे से एक था बंधकों की रिहाई और दूसरा था हमस का उन्मूलन। युद्ध नौ महीने पहले शुरू हुआ और अब तक केवल सात बंधकों को सक्रिय रूप से आईडीएफ द्वारा छुड़ाया गया है। यह भी संभव है कि यह दुर्घटनावश हुआ हो। युद्ध के माध्यम से हमस द्वारा आईडीएफ को एक भी बंधक नहीं सौंपा गया। आक्रमण से पहले नेतन्याहू सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि गाजा में लगभग 25,000 से 30,000 हमस गुरिल्ला हैं। लेकिन नौ महीने के युद्ध के बाद भी, गुरिल्लाओं का 1% न तो मारे गए है और न ही गिरफ्तार हुए हैं । इस समय इजराइल पर घरेलू दबाव दिन–ब–दिन बढ़ रहा है। एक सप्ताह पहले, यानी जून 2024 के तीसरे सप्ताह में, छह सदस्यीय युद्ध कैबिनेट में से दो ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि एक सेना प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इजराइली सेना हमस को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि हमस केवल एक सेना बल नहीं है, बल्कि एक 'विचारधारा' है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक गाजा में आखिरी व्यक्ति जीवित है, हमस वहां जीवित रहेगा।

अब इजराइल एक संकटग्रस्त राज्य

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भारतीय रेल- निजीकरण की तैयारी में रेल यात्रा का

अपर्णा

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा भारत के समृद्ध प्राकृतिक व अन्य संसाधनों को लूटने, श्रमिकों को स्थानांतरित करने और अपना शासन बनाए रखने हेतु दमनकारी ताकतों के हस्तांतरण के लिए भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। यह आज भी भारत के शासक वर्गों के लिए इस भूमिका को निभा रही है। भारत के लोगों के लिए यह एक जीवनधारा बनी हुई थी, आजीविका गंतव्यों तक पहुंचने के लिए और आजीविका की जरूरतों से बिखरे हुए परिवारों को एक साथ अपने जीवन को बुनने की सुविधा देने के लिए भी। यह अधिकांश लोगों के लिए लंबी दूरी के परिवहन का सबसे सस्ता और अक्सर एकमात्र साधन है। यह उन सभी विफलताओं के बावजूद है जो उत्तरोत्तर केंद्र सरकारों की सामान्य जनविरोधी नीतियों के कारण पैदा हुईं।

'नई' आर्थिक नीतियों और डब्ल्यूटीओ शासन के बाद अस्थायी अनौपचारिक नौकरियाँ आम बात हो गईं और ग्रामीण संकट बढ़ गया। फिर भी लोगों की जीवन रेखा के रूप में यह चरित्र पिछले दस वर्षों में लागू की गई नीतियों के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जबकि कृषि आय स्थिर है और कृषि संकट जारी है, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लिए नियमित प्रवास की संख्या का विस्फोट हो गया है। पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से दक्षिण और पश्चिम भारत की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। इन पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा शामिल हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग आम तौर पर अस्थायी, निर्माण उद्योग में रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र में, आईटी उद्योग में और कम वेतन वाली अनौपचारिक सेवाओं में रोजगार के लिए यात्रा करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से शहरी रोजगार के साथ–साथ मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण श्रमिकों के लिए उत्तर की ओर पलायन हो रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पलायन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे महानगरीय शहर और हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य श्रमिकों के लिए गंतव्य हैं। महाराष्ट्र जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों से, और मध्य भारत से कृषि श्रमिकों का दक्षिण की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हर साल हो रहा है (जैसा कि छत्तीसगढ़ के एक 12 वर्षीय प्रवासी की मौत से पता चला है, जो कोविड–19 के दौरान तेलंगाना से पैदल लौट रही थी, जहां उसका परिवार मिर्च तोड़ने के लिए प्रवास किया था)।

अस्थायी कार्यस्थलों और मूल जिलों के बीच भारत के लोगों का यह विशाल आवागमन मुख्य रूप से भारतीय रेलवे पर निर्भर है। यह एक ऐसी सेवा है जिसका हमारे लोगों के लिए महत्व कम नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि यह देश में विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का सबसे सुविधाजनक, सुलभ और सस्ता साधन बना हुआ है।

हालांकि रेल हमारे लाखों लोगों, ज्यादातर श्रमिक वर्ग और ग्रामीण गरीब प्रवासियों के जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है, पिछले लगभग एक दशक में, इस सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागत में कटौती की नीतियों और निजीकरण और मुख्य रूप से निगमीकरण के लक्ष्य को अपनाया गया है, जिसने अपरिहार्य रेल यात्रा को एक अमानवीय अनुभव बना दिया है। यह स्थिति आम लोगों और नागरिक के रूप में उनके आत्म–सम्मान और अधिकारों के प्रति केंद्र सरकार की अवमानना को दर्शाती है।

ये परिवर्तन आकस्मिक नहीं हैं और न ही 'जनसंख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि' के कारण हैं, जैसा कि केंद्र सरकार के समर्थक प्रचारित करते हैं। संख्या में विस्फोट जनविरोधी 'विकास' नीतियों के कारण है। प्रतिक्रिया में कम से कम केन्द्र सरकार को लोगों की मदद के लिए परिवहन सुविधाएं विकसित करना चाहिए और इसमें सार्वजनिक धन बड़ी मात्रा में खर्च करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि योजना जानबूझकर विपरीत दिशा में तैयार की जा रही है। यह दिशा निजीकरण के पक्ष में जमीन तैयार करने की है। इसके लिए शासक दो तरह के कदम उठा रहे हैं। एक है कि सरकारी सेवाएं अक्षम और असफल हैं और इसलिए परेशान जनता को समझाया जा रहा है कि रेल का निजीकरण किया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक उपक्रमों में यही तर्क अपनाया गया है। दूसरा कदम यह है कि सभी यात्री पक्षधर सुविधाओं में कटौती कर दी जाए और सब्सिडी को न्यूनतम कर दिया जाए। यह केवल कॉरपोरेट को आकर्षित करने के लिए है।

स्लीपर की जगह एसी कोच

आरंभ में इस परिणाम को प्राप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ट्रेनों की कोच संरचना। हमारी नियमित ट्रेनों में गार्ड कोच, पावर कोच, पेंट्री आदि सहित 22 बोगियां होती हैं (वंदे भारत, तेजस आदि को छोड़कर)। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेनों में स्लीपर कोच और जनरल कोच की संख्या में तेजी से कटौती की गई है। जबकि एसी कोचों की संख्या बढ़ गई है। (बाद में लेख में यह दिखाया जाएगा कि यह न केवल लाभ कमाने के लिए है बल्कि लागत में कटौती का एक महत्वपूर्ण उपाय भी है।)

कुछ साल पहले तक, प्रत्येक ट्रेन में 11 से 13 स्लीपर कोच और कुछ एसी कोच, खासकर थर्ड एसी कोच होते थे। बेशक इसका कारण यह है, जैसा कि 16 नवंबर 2023 के एचटी इंगलिश पेपर में प्रकाशित एक अध्ययन में दिखाया गया है, यात्री यात्रा की वास्तविकता यह है कि "अप्रैल और अक्टूबर 2023 के बीच 390. 2 करोड़ ट्रेन यात्रियों में से 95.3 फीसदी सामान्य और स्लीपर कोच में थे और एसी कोचों में 4.7 फीसदी।"

हमारी ट्रेनों के कोच कपूरथला, रायबरेली और चेन्नई (आखिरी को आईसीएफ भी कहा जाता है) में तीन रेलवे कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) में निर्मित होते हैं। 27 नवंबर 2023 को वायर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2020 (कोविड 19 अवधि) में रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल यह था कि 22 कोच वाली ट्रेन की कोच संरचना में छह 3एसी कोच, दो 2एसी कोच, 7 स्लीपर कोच और 4 अनारक्षित कोच होंगे। जून 2022 में शेड्यूल को 2 स्लीपर कोच, दस 3एसी और ई एसी कोच, चार 2एसी कोच और सामान्य कोच का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अक्टूबर 2023 आते–आते जैसे–जैसे कोविड 19 का प्रभाव समाप्त होता गया, ट्रेन यात्रा फिर से शुरू हो गई और स्लीपर कोचों की कमी महसूस हुई, तो रेलवे बोर्ड को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा और उसने अपना रुख बदल दिया और अक्टूबर 2023 में (14 अक्टूबर आधिकारिक परिपत्र की तारीख है) एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें 6–7 स्लीपर कोच, 4 जनरल और बाकी एसी और अन्य रूटीन कोच मिलाकर कुल 22 कोच थे।

वहीं, तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 16 नवंबर 2023 को एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि नए एलएचबी कोच पेश किए जाने (यानी 2020) के बाद से ट्रेनों की मानक संरचना अपरिवर्तित थी और ट्रेनों के 22 कोचों में रूटीन के अलावा 6–7 स्लीपर कोच, 4 जनरल, दो सेकेंड एसी, छह 3एसी कोच होंगे। यह अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कोविड से पहले के वर्षों से स्लीपर और जनरल बोगियों की संख्या में कितनी भारी कटौती की गई है। महामारी की अवधि का उपयोग ट्रेनों की भारी कटौती और उनमें कोचों की नई संरचना को स्थापित करने के लिए किया गया था।

कोच निर्माण के लिए हमारी रेलवे कोच फैक्ट्रीज (आरसीएफ) को दिए गए शेड्यूल में यह अच्छी तरह से दर्शाया गया है। रेलवे के सभी ट्रेन कोच इन्हीं तीन फैक्ट्रियों में बनते हैं। जून 2022 के शेड्यूल में, जनरल और स्लीपर कोचों को घटाया गया था (27 नवंबर 2023 को वायर रिपोर्ट जिसमें यह भी कहा गया था कि उन्होंने 2023–24 और 2024–25 का शेड्यूल देखा था)। 2023 शेड्यूल में आम विभाजन है 1142 स्लीपर और जनरल बोगियां और 3044 एसी बोगियां। पहली श्रेणी में प्रत्येक दो साल के लिए 438 सामान्य बोगियां (दीन दयालु) और 704 स्लीपर बोगियां हैं।

एसी बोगियों में से एसी 3 ई बोगियां 2253, एसी 3 बोगियां 402 और एसी 2 बोगियां 389 हैं। भले ही मंत्री की घोषणा के बाद स्लीपर और जनरल बोगियों की नई संख्या (यानी जून 2022 और नवंबर 2023 के बीच बदले हुए आंकड़े) को बदल दिया गया हो। कपूरथला के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वंदे साधारण ट्रेनों की शुरुआत के कारण 12 स्लीपर और 8 जनरल बोगियों की जरूरत है।

जनरल और स्लीपर कोचों में जानबूझकर की गई कमी को साबित करने के लिए पर्याप्त और अधिक तथ्य उपलब्ध हैं। 21 अक्टूबर 2023 को, ऑनलाइन साइट द न्यूज मिनट ने सैकिरण नेतिनी का एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें एक आरटीआई पर दक्षिण पूर्वी रेलवे की प्रतिक्रिया दी गई है। इससे पता चलता है कि 2009 और 2022 के बीच कुल मिलाकर स्लीपर कोचों की हिस्सेदारी 73–79 फीसदी से घटकर 51–56 फीसदी हो गई, यानी 23 फीसदी की गिरावट! आरटीआई से पता चला तीन ट्रेनों के आंकड़े बेहद खास हैं। हावड़ा बेंगलुरु रूट पर 2009 में स्लीपर कोच 79 फीसदी और एसी 21 फीसदी थे, 2014 में यह अभी भी 79 फीसदी और 21 फीसदी थी। 2019 में यह संख्या 64 और 36 फीसदी हो गई। 2022 आते–आते यह 51 फीसदी स्लीपर कोच और 49 फीसदी एसी।

इसी तरह से हैदराबाद–हावड़ा रूट पर आंकड़े निम्न प्रकार हैं, 2009 तक हर ट्रेन में 79 फीसदी स्लीपर और 21 फीसदी एसी, 2014 में 71 फीसदी स्लीपर और 29 फीसदी एसी, 2019 में फिर 79 फीसदी और 21 फीसदी और 2022 आते–आते 55 फीसदी स्लीपर और 45 फीसदी एसी। हावड़ा–चेन्नई रूट पर आरटीआई सूचना के अनुसार 2009 में 73 फीसदी स्लीपर और 27 फीसदी एसी कोच थे, जो 2014 में 64 फीसदी स्लीपर और 36 फीसदी एसी हो गये, जबकि 2019 में 65 फीसदी स्लीपर और 35 फीसदी एसी थे, जबकि 2022 आते–आते 56 फीसदी स्लीपर और 44 फीसदी एसी हो गये।

स्लीपर कोच घटाने से दोहरा लाभ

अब यह पता चल सकता है कि स्लीपर कोच घटाने से सरकार को कितना लाभ होगा। यह तुरंत दिमाग में आता है कि अधिक कमाई होगी, लेकिन एसी कोचों को अटेंडेंट, बिस्तर, एसी रखरखाव आदि की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित उदाहरण से तर्क और भी गहराई से स्थापित हो जाता है। हावड़ा/शालीमार से चेन्नई के लिए केवल दो दैनिक ट्रेनें हैं। 12839 चेन्नई मेल है और 12841 कोरामंडल एक्सप्रेस है। इन दोनों ट्रेनों में अब 3 सामान्य कोच, 3 स्लीपर कोच और 14 एसी कोच हैं (आठ 3 एसी हैं, 2 एसी 3ई हैं, तीन 2 एसी हैं और एक फर्स्ट एसी है)। सप्ताह में एक बार 19 आम कोचों के साथ एक अंत्योदय ट्रेन है (पूरी अनारक्षित)। जिसके सभी डिब्बे आमतौर पर खचाखच भरे रहते हैं। कुछ साप्ताहिक ट्रेनें सप्ताह में 5 दिन चलती हैं। इस रूट पर सभी ट्रेनें यात्रियों से भरपूर, अपनी सीमा से कहीं अधिक भरी हुई चलती हैं और इस रूट पर कई और नियमित ट्रेनों की जरूरत है।

ट्रेन नंबर 12839/12841 में प्रति कोच रेलवे की कमाई स्लीपर में (695 × 80 बर्थ) 55,600 रुपये है। 3 एसी कोच में यह (1825 × 72 बर्थ) 1,31,400 रुपये है। यह वास्तव में कहानी का केवल एक हिस्सा है। प्रत्येक स्लीपर में कम से कम 40 प्रतीक्षा सूची वाले यात्री होंगे, जिससे न्यूनतम 27,800 रुपये अधिक मिलेंगे। और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि प्रत्येक स्लीपर में जनरल टिकट वाले 40 अतिरिक्त यात्री होंगे जो स्लीपर कोच में यात्रा करने के लिए शुल्क अदा करेंगे। इस प्रकार, कुल मिलाकर, प्रति भरी हुई स्लीपर बोगी की कुल कमाई एक लाख रुपये या उससे अधिक तक पहुंच जाती है, जिसमें बिस्तर या परिचारक की कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती, न ही बाथरूम या कोच को साफ करने की कोई आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी बाथरूम और मार्ग ठसाठस भरे रहते हैं और यात्री ऐसी दयनीय और अमानवीय स्थितियों में यात्रा करने पर मजबूर होते है। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और विकलांगों की हालत बहुत ही खराब होती है, यहां तक कि भीड़ के कारण बाथरूम भी पहुंच

अमानवीयकरण!

से बाहर होते हैं या उपयोग से परे, गंदे पड़े हैं और वैसे भी कि युवा पुरुष यात्रियों के लिए भी यह यात्रा करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है।

कोचों को पुनः डिजाइन किया गया

दूसरा मुद्दा खुद कोच से जुड़ा है। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोच भारत में निर्मित होते हैं, पहले उपयोग किए जाने वाले कोच स्विस आईसीएफ कोच थे (चेन्नई की इंटिगरल कोच फैक्ट्री में निर्मित)। 2018 से अकेले नए एलएचबी कोच बनाए जा रहे हैं और 2020 से उपयोग में आ गए हैं। ये जर्मनी द्वारा विकसित लिंके हॉफमैन बुश कोच हैं। वे ICF कोचों की तुलना में अधिक चपटे और लंबे हैं और लगभग 160 किमी/घंटा की तेज गति के लिए डिजाइन किए गए हैं। नए कोच स्टेनलेस स्टील के हैं और इनमें पुराने शॉक एब्जॉर्बर नहीं हैं। इन बोगियों में जगह की भारी कमी के खिलाफ लोगों के आक्रोश के बावजूद सरकार नई इकोनॉमी 3एसी (3ई) कोचों पर जोर दे रही है। यात्री सुविधा एजेंडे में है ही नहीं। एलबीएच कोच एक और लाभ प्रदान करते हैं – प्रति कोच अधिक बर्थ। आईसीएफ कोच में स्लीपर बर्थ की संख्या 72 जबकि एलबीएच में 80 है। थ्री एसी में संख्या 64 से बढ़कर 72, सेकेंड एसी में 46 से बढ़कर 54 कर दी गयी।

क्या वेंडरों पर प्रतिबंध यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है?

सरकार द्वारा व्यावसायीकरण की ओर बढ़ाया गया एक और बड़ा क्षेत्र ट्रेनों में पेंट्री और रेलवे प्लेटफार्मों पर वेंडिंग है। ये सभी आईआरसीटीसी के अधीन हैं जो ट्रेनों में भोजन आपूर्ति का ठेका देता है। प्लेटफॉर्म वेंडिंग का अनुबंध या तो बड़ी श्रंखलाओं से किया जाता है या विक्रेताओं को आईआरसीटीसी की मानक दरों पर छोटी दुकानें चलाने का लाइसेंस दिया जाता है। सभी ट्रेनों – रूटीन, स्पेशल, शताब्दी, राजधानी – में नियमित भोजन की कीमतें अधिक हैं, गुणवत्ता बेहद खराब है। इससे रास्ते में आने वाले कुछ शहरों में निजी कैटरर्स द्वारा यात्रियों को लूटने की सुविधा मिलती है, जो यात्रियों को अच्छा खाना देने का वायदा करते हैं और खराब गुणवत्ता वाला भोजन बेचते हैं, और जिसे वे मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि चलती ट्रेन में ऑर्डर लिया जाता है और निर्धारित स्टॉप पर जल्दबाजी में भोजन सौंप दिया जाता है। जनता खाना (पूरियां और कुछ सूखी सब्जियां जिनकी कीमत 20 रुपये है) को विक्रेता अपने स्टालों द्वारा प्लेटफार्मों पर शायद ही कभी प्रदर्शित करते हैं। ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर हॉकरों और विक्रेताओं का प्रवेश वर्जित है। तर्क यह था कि वे अस्वच्छ हैं, खराब गुणवत्ता वाला भोजन बेचते हैं, आदि। लेकिन सभी यात्रियों को पता है कि चलती ट्रेन में छोटे–मोटे फेरीवाले और विक्रेता होते हैं – वे ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों/पुलिस को पैसा देकर चल पाते हैं।

(यह लेख का पहला भाग है। इसका दूसरा व अंतिम भाग अगले अंक में छपेगा।)

क्या गाजा 'शक्तिशाली' इजराइल का कब्रिस्तान बनेगा?

(पृष्ठ 3 का शेष)

है। जंग के खर्चे के चलते नए कर लगाए जा रहे हैं जिसके खिलाफ जनता में गुस्सा है। जो अब सड़कों पर उतर रहे हैं। हाल ही में, इजराइल में कई विरोध रैलियाँ हो रही हैं जिसमें युद्ध समाप्त करने की मांग की जा रही है। 22–6–2024 को, तेल अवीव, इजराइल की पुरानी राजधानी, में एक बड़ी विरोध रैली हुई, जिसमें 1,50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। फिर 24–6–2024 को वर्तमान राजधानी यरूशलेम में एक और रैली हुई, और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। अब इजराइली लोग मुख्य रूप से तीन मांगों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। उनमें से एक प्रमुख मांग है कि युद्ध को तुरंत रोका जाए। दूसरी मांग है कि अस्थिर गठबंधन सरकार को तुरंत भंग किया जाए और नए चुनाव कराए जाएं। तीसरी मांग है कि युद्ध के नाम पर लगाए गए नए करों को वापस लिया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, इजराइल राजनीतिक रूप से अलग–थलग पड़ रहा है।

सबसे ताजा रिपोर्टों के अनुसार, गाजा के समर्थन में कई और युद्ध मोर्चों की योजना बनाई जा रही है। लेबनान स्थित हिज्बुल्लाह अब इजराइल के खिलाफ एक पूर्ण युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका इसे अपने स्तर पर रोकने की कोशिश कर रहा है। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और उस पर घरेलू दबाव भी हैं। यदि युद्ध लाल सागर या लेबनान तक फैलता है तो अमेरिका को और अधिक गंभीर स्थिति और बोझ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका इसे रोकने में असमर्थ है। पहले से ही इजराइल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह लेबनानी सीमा पर एक और युद्ध मोर्चा खोलने के लिए सेना बलों को जुटा रहा है। यह अमेरिका की असमर्थता का संकेत है। इसलिए, हिज्बुल्लाह के साथ किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है।

लाल सागर क्षेत्र की बात करें तो वहां संकट गहरा रहा है और आगे बढ़ रहा है। दो दिन पहले, यानी जून के चौथे सप्ताह में, एक खबर के मुताबिक अल शदाब, सोमालिया का एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, शक्तिशाली सशस्त्र समूह जो अल–कायदा से सम्बंधित है, ने हौथियों से हाथ मिलाया है। सोमालिया के सशस्त्र समूह तब चर्चा में आए जब 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जो "ऑपरेशन रिस्टोर होप" के हिस्से के रूप में सोमालिया भेजे गए थे। यदि अलशदाब का समर्थन मिलता है, तो हौथी गुरिल्लाओं की सैन्य शक्ति बढ़ सकती है। सोमालिया अफ्रीका के हॉर्न में खाड़ी अदन के पास स्थित है। यह राजनीतिक व रणनैतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है।

हौथी गुरिल्ला संगठन ने अपनी गतिविधियों को लाल सागर क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा है। अब यह दूर तक फैल रहा है। कुछ दिन पहले, इराकी इस्लामी उग्रवादी समूहों के सहयोग से, इसने पहली बार मेडिटेरेनियन सागर के हैफा पोर्ट के पास इजराइल के नौसैनिक सेना अड्डे पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। यह संकेत है कि इजराइल अब युद्ध के जाल में फंस रहा है।

उबलती हुई अरब सड़कों पर कभी भी विस्फोट हो सकता है। 2011 में अरब स्प्रिंग के समय, ट्यूनीशिया और मिस्र में अप्रत्याशित विद्रोह हुए थे। गाजा अब कुछ अरब देशों की राजशाही सरकारों को आतंकित कर रहा है। इसलिए वे पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि अमेरिका ने लाल सागर में हौथी गुरिल्लाओं के खिलाफ दस देशों के साथ एक सेना गठबंधन बनाया, लेकिन कोई भी प्रमुख अरब देश इसमें शामिल नहीं हुआ। ईरान अब खुलेआम अमेरिका के सहयोगी इजराइल का विरोधी है, लेकिन अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने या उसे घेरने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोई भी अरब देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। असली कारण यह है कि खून बहाता हुआ गाजा आग में घी डालने का काम कर रहा है।

ईरान के नेतृत्व वाली प्रतिरोध धुरी अब इजराइल को गाजा से बाहर निकालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, इराक में ईरान समर्थक गुरिल्ला समूह भी जायनिस्ट इजराइल के खिलाफ पूर्ण युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं।

दो दिन पहले, यानी जून के अंत में, वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब आईडीएफ के हिंसक सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, तो आईडीएफ बलों के खिलाफ अचानक, तेज, फ्लैश गुरिल्ला हमला हुआ, जिसमें 17 आईडीएफ सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह स्पष्ट संकेत है कि सशस्त्र प्रतिरोध का वर्तमान क्षेत्र अब वेस्ट बैंक तक फैल चुका है। वेस्ट बैंक अब तक एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र रहा है लेकिन गाजा की विपरीत यह सशस्त्र संघर्ष का क्षेत्र नहीं था। ओस्लो समझौते के बाद, पीएलओ ने आधिकारिक रूप से सशस्त्र रास्ते को छोड़ दिया। यह वेस्ट बैंक को नियंत्रित करता है। हाल के वर्षों में, फतह को धीरे–धीरे वेस्ट बैंक के लोगों के दिलों से हमस द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यहां भी हमस का सशस्त्र संघर्ष अब आकार ले रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में, हम अनुमान लगा सकते हैं कि वेस्ट बैंक भी धीरे–धीरे गाजा के साथ–साथ जायनिस्ट इजराइल के लिए एक कब्रिस्तान में परिवर्तित हो रहा है।

हाल ही में राफा भी गाजा के लोगों के घाव और पीड़ा का एक बहुत ही लोकप्रिय प्रतीक बनता जा रहा है। राफा को एक कब्रिस्तान में बदल दिया गया है लेकिन इसे एक गुरिल्ला क्षेत्र में भी परिवर्तित किया जा रहा है। वास्तव में, हाल के समय में यहाँ बार–बार सशस्त्र हमले हुए हैं। राफा में कई मौकों पर आईडीएफ सैनिक भी पराजित हुए हैं। नेतन्याहू सरकार राफा को हिब्रू भूमि में बदलना चाहती है, जो जायनिस्ट एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन जमीनी हकीकत अब दूसरी दिशा में जा रही है और राफा भी इजराइली सेना के लिए एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है।

रूस व चीन ने हाल ही में इस युद्ध के संबंध में कुछ कदम उठाए हैं। अब फ्रांस और जर्मनी सक्रिय रूप से अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कई ई.यू. सदस्य देश भी या तो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं या उससे दूरी बना रहे हैं।

यह समय है कि हम एक बार फिर गाजा के सशस्त्र मार्ग और उसके मशाल वाहक हमस की भूमिका पर कुछ मार्क्सवादी संगठनों के विश्लेषण के बारे में विचार करें। कुछ यूरोपीय मार्सवादी लेनिनवादी पार्टियां हमस को एक आतंकवादी समूह मानती हैं। एक ओर, कुछ तथाकथित मार्क्सवादी लेनिनवादी गुट और बुद्धिजीवी हमस को गाजा के लोगों से अलग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर, इजराइली सेना प्रमुख स्पष्ट रूप से इस कड़वे सच को महसूस कर रहे हैं कि हमस सिर्फ एक सेना शक्ति नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी लोगों के मुक्ति संघर्ष की 'विचारधारा; है। जो कुछ भी बमेरिका ने पहले कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में झेला, वही अब इजराइल भी छोटे से गाजा में झेल रहा है। वास्तव में, वियतनाम, कोरिया में घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। अफगानिस्तान में पहाड़ी क्षेत्र और विशाल घाटियां होती हैं। इराक में शायद जंगल और घाटियां न हों, लेकिन वहां विशाल क्षेत्र है। सबसे आश्चर्यजनक बात गाजा बेहद छोटा है।

दुनिया के सशस्त्र संघर्षों के इतिहास में, गाजा की बहादुर जनता एक अनूठा अध्याय लिख रही है। उन्होंने सुरंगों का उपयोग अपने संघर्ष के मुख्य स्वरुप में किया है। पहले के सशस्त्र क्रांतियों में भी भूमिगत सुरंगों का उपयोग किया गया, लेकिन नेताओं की सुरक्षा के लिए। इसके विपरीत गाजा में छापामार युद्ध को चलाने के लिए सुरंगों का गहन जाल बनाया। यह पहली बार है जब गाजा के लोगों ने दुनिया में एक नया भूमिगत संघर्ष का रूप बनाया है। वास्तव में, अभी तक हुए सभी भूमिगत सशस्त्र क्रांतियाँ राजनीतिक रूप से भूमिगत थीं लेकिन भौगोलिक रूप से भूमि पर थीं। परंतु गाजा का सशस्त्र संघर्ष सुरंगों के जाल के माध्यम से लड़ा जा रहा है। इसलिए, यह न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि भौगोलिक रूप से भी एक भूमिगत सशस्त्र संघर्ष है। साढ़े तीन लाख आबादी वाली शक्तिशाली भूमिगत आईडीएफ सेना भी नौ महीने की घेराबंदी के बावजूद भी हमस सेना को नहीं ढूंढ पाई है, जो 365 वर्ग किलोमीटर और दुनिया के आठवें चमत्कार वाले सुरंगों के विस्तृत जाल को दर्शाता है।

गाजा की जनता सिद्ध कर रही है कि सशस्त्र क्रांतियाँ अब भी प्रासंगिक हैं। वे यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि किसी बड़े भूमि क्षेत्रों के बिना भी आक्रमणकारियों, आक्रमकों और घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास रचा जा सकता है। इस छोटे से भूमि क्षेत्र के लोगों ने अपनी जान का जोखिम उठाते हुए उनके खिलाफ अनेकों मुश्किलों के बावजूद क्रांतिकारी इतिहास में एक नया अध्याय बनाया है। हम उन्हें नमन करते हैं।

फिलिस्तीन अमर रहे!

क्रांति अमर रहे!

(न्यू डेमोक्रेसी के जुलाई 2024 अंक में प्रकाशित लेख का अनुवाद)

3 आपराधिक कानूनों को निरस्त करने की मांग पर तमिलनाडु के वकीलों द्वारा प्रदर्शन

ज्वाइंट एडवोकेट्स एसोसिएशन काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी के बैनर तले तमिलनाडु के अधिवक्ताओं ने 3 नए कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी के जंतर–मंतर पर गत 29 जुलाई 2024 को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया।

विरोध प्रदर्शन में लगभग 2000 वकील, जिनमें तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से महिला वकील भी शामिल थीं, उपस्थित थे। उन्हें जेएएसी के सदस्यों ने संबोधित किया, जिसमें जेएसी सदस्य एडवोकेट राजू, जो पीपुल्स पावर तमिलनाडु के नेता हैं, तमिलनाडु बार काउंसिल के सदस्य, तमिलनाडु के विभिन्न जिला बार एसोसिएशन के नेता, तमिलनाडु के कई संसद सदस्य, अधिवक्ता राजीव खोसला और संजीव नासियार, जो दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य हैं, सेक्रेटरी जनरल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दिल्ली बार एसोसिएशन शामिल थे।

प्रगतिशील महिला संगठन (पीएमएस) दिल्ली की महासचिव पूनम कौशिक ने भी एकजुटता भाषण दिया। जेएएसी को उनकी पहल के लिए, उनके प्रभावी पोस्टरों के लिए बधाई दी गई, जिसमें कठोर, जनविरोधी प्रभाव और 3 नए कानूनों के प्रावधानों को सरल नारों में वर्णित किया गया था। यह याद करते हुए कि कैसे किसानों ने अपने निरंतर, दृढ़ संघर्ष और बलिदान के माध्यम से फासीवादी मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर किया, उन्होंने उम्मीद जताई कि देश भर के वकील इस केंद्र सरकार को 3 नए आपराधिक कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर करने के लिए संघर्ष का नेतृत्व करेंगे।

(बायें – सभा को संबोधित करतीं का. पूनम कौशिक तथा नीचे – वकीलों की विरोध सभा)

का. रायला चन्द्रशेखर को श्रद्धांजलि

सीपीआई (एमएल)– न्यू डेमोक्रेसी कामरेड रायला चंद्रशेखर (आरसीएस) की असामायिक तथा दुखद मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करती है। वह सीपीआई (एमएल) मास लाइन के केंद्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष थे।

कामरेड आरसीएस छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर आकर्षित हुए और तब से क्रांतिकारी आंदोलन में बने रहे। वह खम्मम जिले के पिंडीपोरलू गांव के निवासी थे और उनके परिवार के कई सदस्यों ने क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन में अग्रणी भूमिका निबाही तथा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियो का निर्वाह किया, जिनमें उनके बड़े भाई कामरेड रवि शामिल हैं जो 2016 में अपनी मृत्यु के समय सीपीआई (एमएल)– न्यू डेमोक्रेसी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य थे। कामरेड आरसीएस लगभग 28 वर्षों तक पहले आंध्र प्रदेश और फिर राज्य विभाजन के बाद सीपीआई (एमएल) न्यू डेमोक्रेसी की तेलंगाना राज्य समिति के सदस्य रहे। अपनी मृत्यु के समय लगभग 68 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में लगभग पांच दशक बिताए।

कामरेड आरसीएस ने एजेंसी आंदोलन में लंबे समय तक काम किया। उन्होंने पार्टी के सामने आने वाले कठिन कार्यों को स्वेच्छा से संभाला और हमेशा गर्म जोशी से लबरेज थे। वह तेलंगाना में किसान आंदोलन के परिचित नेता रहे।

सीपीआई (एमएल)– न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति कामरेड आरसीएस को श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनकी पत्नी, पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों और उनके साथियों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

सीपीएम (एमएल)– न्यू डेमोक्रेसी

18–7–24

का. आरसीएस 2016 में ए.आई.के.एम.एस. की केन्द्रीय कार्यकारिणी के लिए चुने गये थे। उनके निधन पर ए.आई.के.एम.एस. की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृति में एक प्रस्ताव पारित किया।

2024–25 बजट पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) का बयान

– नियमित कॉरपोरेट पक्षधर बजट

– भारतीय कॉरपोरेट के 'अतिरिक्त मुनाफे में तैरने' और बैंक के लाभ के 'कई वर्षों के उच्चतम स्तर' पर पहुँचने के बावजूद मुद्रास्फीति, नौकरियों, कर्जों पर लोगों को कोई राहत नहीं।

– प्राकृतिक खेती का नुस्खा उत्पादन में गिरावट, खाद्य संकट, आपदा की आशंका को बढ़ावा दे रहा है।

– केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए भूमि और फसल पंजीकरण के साथ केंद्रीय सहकारी नीति, कृषि पर राज्य के अधिकार और खतरे में।

– रोजगार सृजन के लिए कोई भौतिक प्रोत्साहन नहीं, मनरेगा खर्च में कटौती।

– बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को राहत देने के लिए निगम कर घटाकर 40 फीसदी से 35 फीसदी किया।

कृषि गहरे संकट में है और बजट घोषणाएं 2 साल के भीतर 1 करोड़ किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती में लाने के प्रस्ताव के साथ बड़ी आपदा का डर पैदा करती हैं। इन्हें ग्राम प्रधानों के माध्यम से संगठित कर 'ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग' का लाभ दिया जायेगा। प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के क्षरण और विशाक्तता के नाम पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। आर्थिक सर्वेक्षण में उर्वरक बिक्री के लिए ई–आरयूपीआई योजना पर प्रकाश डाला गया है जिसमें सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री केवल 'वास्तविक' किसानों को या उनकी संस्तुति द्वारा दी जाएगी और भूमि की गुणवत्ता के अनुसार सीमित खरीद की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य उर्वरक सब्सिडी को घटाकर केवल 70 फीसदी बोए गए क्षेत्र तक सीमित करना है।

इससे 2022 में श्रीलंका जैसा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा और खाद्य उत्पादन में लगभग 50 फीसदी की भारी गिरावट आएगी। लाखों भारतीय हर दिन भूखे पेट सोते हैं। उर्वरक सब्सिडी में की गयी कटौती, जिसे वर्ष 2021–22 में 2.52 लाख करोड़ रुपये से घटाकर इस साल 1.64 कर दिया गया है और प्राकृतिक खेती से भूख और भुखमरी की समस्या बढ़ेगी।

बजट में किसानों को एमएसपी पर कोई राहत नहीं दी गई है, बस दावा किया गया है कि खर्च से 50 फीसदी अधिक एम.एस.पी. की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। धान का एमएसपी अब 2300 रुपये प्रति क्विंटल है और इसकी केवल 5.33 फीसदी की वृद्धि की थी, जो कि खाद्य मुद्रास्फीति, 10 फीसदी की तुलना में बहुत कम है और भाजपा के चुनावी वायदे 3100 रुपये प्रति क्विंटल से भी। भारतीय कॉरपोरेट के 'अतिरिक्त मुनाफे में डूबने' और बैंक के हितों के 'कई वर्षों के उच्चतम स्तर' पर पहुंचने के बावजूद, मोदी सरकार ने एमएसपी और कर्ज माफी की किसानों की मांग पर रोड रोलर चला दिया है।

भारी लागत कीमतों, खराब एमएसपी और इससे भी खराब सरकारी खरीद के कारण किसान भारी कर्ज से जूझ रहे हैं। कृषि लागत पर वर्तमान जीएसटी पर भी कोई राहत नहीं दी गई है, जो उर्वरकों पर 18 फीसदी और ट्रैक्टर, उपकरण और स्पेयर पार्ट्स पर 12 फीसदी है और न ही ईंधन पर उच्च वैट और उत्पाद शुल्क पर।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटित व्यय 1,52,851 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से कृषि और किसान कल्याण को केवल 1,22,528 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले वर्ष के 1,16,788 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 4.9 फीसदी की वृद्धि है, इसमें मुद्रास्फीति भी शामिल नहीं है। 1.52 लाख करोड़ रुपये 48.25 लाख रुपये के कुल बजट व्यय का मात्र 3.15 फीसदी है, जबकि यह वित्त वर्ष 20 में 5.44 फीसदी, वित्त वर्ष 21 में 5. 08 फीसदी, वित्त वर्ष 22 में 4.26 फीसदी और वित्त वर्ष 23 में 3.23 फीसदी था। यह बहुत कम है सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर 50 फीसदी आबादी की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा नही कर सकता।

खाद्य सब्सिडी (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) भी पिछले वर्ष के 2.22 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से घटकर 2.13 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। मनरेगा फंड 1.05 लाख करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय से घटकर केवल 86,000 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

सहकारी क्षेत्र का अधिग्रहण : बजट में एक राष्ट्रीय सहकारी नीति का प्रस्ताव है जिसका विवरण बाद में दिया जाएगा, लेकिन इसमें 6 करोड़ से अधिक किसानों और उनकी भूमि और फसल पैटर्न को डिजिटल किया जाएगा। इससे कृषि नीति पर राज्य का अधिकार और खत्म हो जाएगा और कॉरपोरेट द्वारा भूमि और संसाधनों पर कब्जा मजबूत हो जाएगा।

ग्रामीण विकास बजट 2.66 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, लगभग 82,000 करोड़ रुपये की वृद्धि है, पर यह बिना विवरण के है। यह देखते हुए कि कृषि क्षेत्र सिंचाई के बुनियादी ढांचे, विपणन, खाद्य भंडारण, प्रसंस्करण और ग्रामीण विकास के लिए सरकारी समर्थन की मांग कर रहा है और यह तथ्य कि कई घोषणाएं एक–दूसरे में शामिल होती हैं, इस पर बड़े सवाल हैं कि सरकार क्या करना चाहती है।

(ए.आई.के.एम.एस. अध्यक्ष वी. वेंकटरमैया तथा महासचिव आशीष मितल द्वारा जारी)

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

तिलौथू (सासाराम, बिहार) : ए.आई.के.एम.एस. के केन्द्रीय जांच दल की रिपोर्ट

तिलौथू, सासाराम, बिहार में 30 जून 2024 को जमीन की मांग को लेकर संघर्षरत गरीबों पर इलाके के सामंत के लठैतों द्वारा लाठियों से हमले की अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने जांच की। उक्त घटना में कई महिलाएं घायल हुईं और दो पुरुषों को गम्भीर चोटें आईं।

जांच :

एआईकेएमएस के उपाध्यक्ष सुशान्तो झा एवं महासचिव आशीष मित्तल के नेतृत्व में दो सदस्यीय एआईकेएमएस जांच दल ने स्थानीय सासाराम एआईकेएमएस नेताओं अयोध्या प्रसाद, सुरेंद्र सिंह और लोक संघर्ष मोर्चा के संयोजक सुनील कुमार वर्मा के साथ 18 जुलाई को तिलौथू और भदरा का दौरा किया। टीम ने तिलौथू में लगभग 60 निवासियों से बातचीत की, जिनमें से ज्यादातर 7 पड़ोसी गांवों से थे और ज्यादातर महिलाएं थीं।

टीम को तिलौथू में पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की समाप्ति के 70 साल बीत जाने के बावजूद, बिहार के इस पिछड़े इलाके में गरीबों से कर वसूलने के जमींदारी राजस्व अधिकार अभी भी जारी हैं। यद्यपि तिलौथू लगभग 2000 दुकानों का एक पूर्ण बाजार है, जिसमें 4 लेन राजमार्ग गुजरता है, दुकानों में बिजली कनेक्शन है, पूरी जमीन अभी भी ग्राम पंचायतों का हिस्सा है और अब तक कोई बाजार क्षेत्र का भूमि बन्दोबस्त नहीं किया गया है। इस बाजार क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन और तिलौथू का एक प्रखंड विकास कार्यालय है और ये दशकों से अस्तित्व में हैं, फिर भी बाजार क्षेत्र की जमीन की बंदोबस्ती दुकानदारों के नाम पर नहीं की गई है।

यह क्षेत्र तिलौथु एस्टेट के मालिक, पूर्व जमींदार स्वर्गीय राधा प्रसाद सिन्हा के एक शक्तिशाली स्थानीय परिवार की तीसरी पीढ़ी के वंशजों द्वारा राजनीतिक रूप से और राजस्व मामलों के लिए नियंत्रित किया जाता है। स्थानीय और राज्य सरकार तक प्रशासन और पुलिस से उनके गहरे संबंध हैं। वे ही दुकानों से किराये के रूप में राजस्व वसूलते हैं। जिस जमीन पर दुकानें हैं, उसकी बिक्री के नाम पर वे हर कुछ वर्षों में दुकानदारों को भारी रकम देने के लिए भी मजबूर करते हैं, लेकिन बिक्री नहीं की जाती है। कई बार वे जबरन मांगी गई रकम वसूलने के लिए दुकानदारों का सामान बाहर फेंक चुके हैं, लेकिन कभी भी पुलिस या प्रशासन ने उन पर लगाम नहीं लगाई।

जांच के दौरान पता चला कि वर्षों से इस भूमि का कुछ हिस्सा अवैध रूप से बेचा गया है और अब लगभग 29 एकड़ में एक आनंदकुटी धाम पयहारी बाबा आश्रम है और लगभग 3.5 एकड़ में राधा शांता कॉलेज है। ये दोनों ट्रस्टों के स्वामित्व में हैं। यह समझ से परे है कि कैसे कानून के तहत ये ट्रस्ट उस जमीन का मालिक हो सकते हैं जो वास्तव में बिहार सरकार की थी, जिसे गरीबों को वितरित किये जाने के लिए सरकार को दान दी गयी थी। कुल भूमि के 29 एकड़ भूमि पर पूर्व जमींदार राधा प्रसाद सिन्हा के वंशजों ने दो दिशाओं से तार से घेराबंदी कराकर अपना अवैध दखल कब्जा बना रखा है।

लोगों ने बताया कि नितीश सरकार द्वारा गरीबों में आवंटन के लिए बंधोपाध्याय कमीशन का गठन 2004 में किया था और उस रिपोर्ट ने ऐसी हजारों एकड़ जमीन को चिन्हित की थी। पर सत्ता में बने रहने के बावजूद आज तक इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा गया। स्पष्ट है कि 2024 में भी बिहार सरकार जमींदारों द्वारा कानून के ऐसे दुरुपयोग की इजाजत देती है।

जांच दल ने पाया कि उपस्थित सभी प्रतिनिधि, विशेष रूप से महिलाएं अपने संघर्ष के उद्देश्य के बारे में बहुत स्पष्ट थीं। वे समझ रही थीं कि उन्हें सरकार को भूमि स्वामित्व और नियंत्रण देने के लिए एक मजबूत और एकजुट संघर्ष करना होगा। वे क्षेत्र में भूदान भूमि और बिहार राज्य की सैकड़ों एकड़ भूमि के मुद्दों को उठाने के बारे में आश्वस्त दिखे।

पीड़ितों ने खुद बताया कि 30 जून को जब उन्होंने बूढ़ी माई मंदिर में इकट्ठा होना शुरू ही किया था, इस बात से अनजान थे कि उन पर हमला किया जा सकता है, भले ही उन्होंने कोई विरोध शुरू नहीं किया था। उन्होंने बताया कि इलाके के करीब 40 लठैतों ने एकाएक उन्हें घेर पर उन पर हमला शुरु कर दिया और जब कामरेड प्रमोद ने सामने आकर रोकना चाहा तो उन्हें पीटते–पीटते ये लठैत वहां से उठाकर ले गये। ये सभी लठैत पास के जमीन वाले यादव बिरादरी के लोग हैं, जो तिलौथु एस्टेट के भूमाफियाओं, पूर्व जमींदार राधा प्रसाद सिन्हा के पुत्रों के साथ कई गैरकानूनी धंधों में संलिप्त हैं। इलाके में जो भी गिट्टी, बालू, जमीन व शराब बिक्री के धंधे होते हैं इन सब में उनकी मिलीभगत है। इलाके में होने वाली अन्य अपराधिक घटनाओं में भी इन अपराधियों की संलिप्तता रहती है। इनमें मुख्य रुप से सुदामा यादव व उनके पुत्र तथा रामलोचन यादव ने हमले का नेतृत्व किया और इन्हीं के द्वारा दिये गये गरीबों के नामों को पुलिस ने रिपोर्ट में आरोपित बनाया।

जब प्रतिनिधिमंडल एडीएम रोहतास से मिला तो सासाराम रोहतास प्रशासन इन जमीनों की बंदोबस्ती नहीं होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। उनसे अनुरोध किया गया कि गरीब किसानों की नामित एफआईआर के अनुसार आरोपी गुंडों की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि यह पहली बार है कि किसी दबंग परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उक्त एफआईआर संख्या 184/24 को कमजोर करने के लिए पुलिस ने किसानों और नेताओं के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से एक सीओ द्वारा दर्ज की गई है, एक थानाध्यक्ष और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई हैं। ये सभी पीड़ितों की एफआईआर के पहले पंजीकृत की गईं, इनकी संख्या 180, 181 और 182/2024 है।

बाद में टीम लगभग 30 किमी दूर भदारा गांव गई। यहां 8 साल पहले गांव के गरीबों ने बिहार सरकार की 750 एकड़ जमीन में से 55 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिस पर स्थानीय जमींदार खेती करवा रहे थे। बिहार सरकार ने हाल ही में कुछ मालिकों के नाम पर पंजीकृत इन जमीनों के स्वामित्व को अवैध रूप से स्थानांतरित करने का कदम उठाया है। किसान न केवल अपनी भूमि की रक्षा के लिए बल्कि कृषि को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए भी संघर्ष करने के लिए दृढ़ हैं।

एआईकेएमएस जांच दल ने मांग की है कि –

1. तिलौथू की सारी भूदान की जमीन और इलाके में बिहार सरकार की जमीनों को गरीबों और भूमिहीनों के नाम बंदोबस्त कर दखल कब्जा दिया जाए।

2. पयहारी बाबा आश्रम और राधा शांता कालेज की जमीन की ट्रस्ट को रद्द करके जमीन गरीबों के नाम आवंटित की जाए। इन ट्रस्टों के निर्माण की जांच की जाए और दोषी अफसरों को सजा दी जाए।

3. तिलौथू बाजार की सभी दुकानों को दुकानों के मालिकों के नाम बंदोबस्त किया जाए एवं अवैध वसूली रोकी जाए। इलाके को नगर पंचायत दर्ज कर सभी सुविधाएं दी जाएं।

4. गरीबों पर दर्ज मुकदमा संख्या 180, 181, 182/2024 थाना तिलौथू के केस वापस लिये जाएं तथा गरीब भूमिहीनों की तरफ से 30 जून 2024 की लठैतों द्वारा हमले की घटना के बाबत दर्ज रिपोर्ट 184/2024 में नामजद गुण्डों को गिरफ्तार किया जाए।

5. भदारा क्षेत्र की 750 एकड़ भूमि की नाप कराकर इलाके के गरीबों में आवंटित की जाए और सिंचाई विभाग द्वारा योजना बनाकर इलाके में सिचाई की व्यवस्था की जाए।

गंजम (ओडिशा) : बांध के खिलाफ प्रदर्शन

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) के नेतृत्व में 23 गांवों के सैकड़ों गरीबों, दलितों और आदिवासियों ने रूशिकुल्या नदी पर बनने वाल वाले पीपल पांका बांध के निर्माण को रद्द करने के लिए 10 जुलाई को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एआईकेएमएस के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों खास तौर पर आदिवासी और दलित समुदाय ने उड़ीसा के गंजम जिले के सोराडा तहसील कार्यालय के सामने आयोजित विरोध सभा में पीपल पांका में महानदी पर प्रस्तावित जलाशय को रद्द करने की जोरदार मांग की। यह परियोजना केवल छतरपुर के पास टाटा कंपनी के औद्योगिक गलियारे में स्थित उद्योगों को 100 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति करने के लिए प्रस्तावित है। यदि इस परियोजना का निर्माण होता है, तो गंजम–कंधमहल सीमा क्षेत्र में स्थित हजारों एकड़ घने जंगलों और जीव जंतुओं के साथ–साथ 23 आदिवासी गांव भी हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएंगे।

गंजम जिले की जीवन रेखा कहीं जाने वाली रूशिकुल्या नदी का पानी जिले के बड़े क्षेत्र को पीने का पानी और सिंचाई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन विभिन्न कारणों से बरसात के 4 महीनों को छोड़कर नदी में अब बहुत ही कम पानी बचा रहता है। इसलिए इसके ऊपरी हिस्से पर बड़ा बांध बनाने से इसकी क्षमता को और नुकसान पहुंचेगा और नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले हजारों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए एआईकेएमएस ने टाटा जैसी निजी कंपनियों के उद्योगों के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए सरकारी खजाने से इस बांध के निर्माण का विरोध करने का फैसला किया है। इस संदर्भ में 10 जुलाई को सैकड़ों लोगों ने सोराडा तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार को एक ज्ञापन सौंप कर इस परियोजना को तुरंत रद्द करने की मांग की है। एआईकेएमएस नेताओं ने ग्रामीणों, दलितों और आदिवासियों की सभा को संबोधित करते हुए मांग की कि गरीब किसानों खासकर दलितों और आदिवासियों को भूमि और वन अधिकार पट्टे देने की भी मांग की। ज्ञापन में सरकार से सोराडा तहसील के सभी वंचित आदिवासी गांवों में जल्द से जल्द पेयजल, बिजली और सड़कों का निर्माण करने का भी आग्रह किया। एआईकेएमएस नेता कामरेड प्रताप नायक, संग्राम, कालीचरण नायक और हरी मल्लिक आदि नेताओं ने विरोध सभा को संबोधित किया।

पंजाब: मृतक मनरेगा मजदूरों के आश्रितों के लिए आंदोलन

पंजाब के नाभा पटियाला प्रशासन और पंजाब सरकार दो मनरेगा श्रमिकों की कार्य के दौरान हुई मौत के बाद पीड़ित परिजनों को एक लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा नहीं करती तब तक एक्शन कमेटी संघर्ष जारी रखेगी। एक्शन कमेटी ने 5 जुलाई 2024 को पंजाब के नाभा ब्लॉक के तुगा गांव में मनरेगा मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष तेज करते हुए आंदोलन के अगले कदमों की घोषणा की।

एक्शन कमेटी के नेता कश्मीर सिंह गुड़ैया, मनरेगा फ्रंट के नेता राजकुमार, जेडपीएससी नेता धर्मवीर सिंह और अंबेडकर कीर्ति संघ के नेता कुलवंत सिंह सरोय ने घोषणा की कि जब तक नाभा पटियाला और पंजाब सरकार मृतक मनरेगा मजदूरों के प्रति गंभीर नहीं होती और और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता तथा नौकरी नहीं देती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञात हो कि नाभा में दो मनरेगा मजदूरों की उस समय मौत हो गई थी, जब काम करते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर उनके ऊपर चढ़ गया था। नाभा के विधायक और एसडीएम नाभा ने धरना स्थल पर आकर नेताओं को मांगे पूरा करने का आश्वासन दिया था। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवारों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मांगे पूरी होने के लिए प्रशासन को आधिकारिक रूप से घोषणा करनी होगी। इस मौके पर आईडीपी नरेगा वर्कर्स यूनियन फिल्लौर, श्री गुरु रविदास सेवा सोसायटी नाभा, क्रिश्चियन यूथ सभा पंजाब, पंजाब निर्माण मजदूर यूनियन, मनरेगा मजदूर यूनियन (सीआईटीयू), पंजाब ट्रेड यूनियन (एटीके) पंजाब आरएमपी सहित अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए मांगे पूरी न होने तक प्रशासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है।

बंगलादेश: शेख हसीना सरकार द्वारा आंदोलनकारी छात्रों पर क्रूर दमन

पीडीएसयू–पीएसयू बंगलादेश के छात्रों के साथ खड़े हैं जो बंगलादेश में हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं। उन पर पुलिस और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समूहों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। 18 जुलाई 2024 तक इन हमलों में 33 से अधिक छात्रों के मारे जाने और 1000 से ज्यादा घायल होने की सूचना है। इसके बाद की घटनाओं में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सभी स्कूल और कॉलेज बंद होने और इंटरनेट पूरी तरह ठप कर दिए जाने के बावजूद पूरे बंगलादेश में विरोध प्रदर्शन फैल गया है और दृढ़ होता जा रहा है।

छात्र 1971 के युद्ध में भाग लेने वालों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ लड़ रहे हैं। अन्य श्रेणियां के लिए अतिरिक्त 26 प्रतिशत आरक्षण है। महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत, पिछड़े जिलों के लिए 10 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 5 प्रतिशत और विकलांगों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण है। छात्र महिलाओं, पिछड़े जिलों, अल्पसंख्यकों और विकलांगों के लिए इन आरक्षणों का विरोध नहीं कर रहे हैं। छात्रों के विरोध को कुचलने के लिए बंगलादेश सरकार द्वारा अपनाए गए दमनकारी उपायों के चलते विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो गये हैं।

बंगलादेश में दो सप्ताह से चल रहा कोटा विरोधी प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े समूहों ने राजधानी ढाका विश्वविद्यालय के साथ–साथ चटगांव विश्वविद्यालय और अन्य जिला विश्वविद्यालयों में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हमले किये। विरोध प्रदर्शन 1 जुलाई को तब शुरू हुआ, जब उच्च न्यायालय ने नौकरी कोटा बहाल कर दिया, जो 1971 में देश के 'मुक्ति योद्धाओं' के वंशजों के लिए सिविल सेवा पदों का 30 प्रतिशत पद आरक्षित करता है। प्रदर्शनकारी इस 30 प्रतिशत कोटा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी लाभ उठा रही है। सरकार ने दंगा निरोधक पुलिस बल तैनात किया है, जिसने प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थक छात्र समूहों के बीच हिंसक झड़पों के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाईं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्रों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक विरोध जारी रखने की घोषणा की है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि युद्ध के इतने लंबे समय बाद युद्ध के दिग्गजों के लिए आरक्षण अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि लगभग 5 दशकों के बाद अब यह तीसरी पीढ़ी है। यह कोटा सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों की सेवा करने का एक साधन बन गया है। सरकारी नौकरियां दुर्लभ हैं और यह आरक्षण कुल सरकारी नौकरियों का लगभग एक तिहाई है। पिछले साल 3000 पदों के लिए चार लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। यह बेरोजगारी की भयावह समस्या को दर्शाता है, जो वर्तमान आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यह बेहतर वेतन वाली और सुरक्षित नौकरियां हैं। शेख हसीना सरकार को 2018 में एक मजबूत छात्र विरोध के बाद इस आरक्षण को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन जून 2024 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस कोटे को पुनर्जीवित कर दिया गया।

पीडीएसयू–पीएसयू इन वैध विरोधों के जवाब में बंगलादेश सरकार द्वारा दिखाई गई बर्बरता की कड़ी निंदा करता है। छात्रों की वैध चिंताओं को संबोधित करने के बजाय अधिकारियों ने गंभीर दमनकारी उपाय का सहारा लिया है। छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य है। ऐसा निहत्थे छात्रों की सभाओं को हिंसक तरीके से तितर–बितर करने, मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने और छात्रों को डराने धमका में देखा गया है। आंदोलन की शुरुआत में ही 33 छात्रों के अलावा लगभग 30 पत्रकार भी पुलिस की गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। शेख हसीना सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित करार दिया है। इस प्रकार छात्रों की मांग की न्यायोचित प्रकृति को पूरी तरह से नकार दिया गया है। सरकार की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वह न्यायालय के आदेश के पीछे थी। 30 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ विरोध के रूप में शुरू हुआ यह प्रदर्शन अपने दमनकारी और गैर जिम्मेदाराना कृत्यों और अलोकतांत्रिक चरित्र के कारण आवामी लीग सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

हम आंदोलनकारी छात्रों के साथ एक जुटता में है और उनके विरोध का समर्थन करते हैं।

19 जुलाई 2024 पीडीएसयू–पीएसयू

बक

केकेयू महिला विंग का सफल सम्मेलन

लोकतांत्रिक व किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका

कीरति किसान यूनियन की महिला शाखा ने 15 जुलाई 2024 को मोगा (पंजाब) में किसान मुद्दों और लोकतांत्रिक एवं किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। यह केकेयू की महिला शाखा की एक सफल पहल थी और इसने बड़े पैमाने पर किसान महिलाओं को संगठित करने के लिए नए रास्ते भी खोले हैं। पंजाब के 10 जिलों की महिलाओं ने इस सम्मेलन में भागीदारी की। भीषण गर्मी व उमस भरे मौसम और धान की रोपाई का मौसम होने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं सम्मेलन में शामिल हुईं। सम्मेलन को महिला शाखा ने स्वतंत्र रूप से आयोजित किया था। हालांकि महिला नेतृत्व अभी भी स्थापित होना बाकी है, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा अभी भी धीरे–धीरे अपने पैर जमा रहा है।

डॉक्टर नवशरण, डॉ अरविंदर काकड़ा और अमनदीप देओल किसान मुद्दों और लोकतांत्रिक एवं किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित सम्मेलन की मुख्य वक्ता थीं। साथ ही महिला शाखा की संयोजक हरदीप कोआला भी थीं। इसके अलावा राजकौर, प्रदीप कौर, जगविंदर कौर, शिंदर पाल कौर, बलिहार कौर, भिंडरपाल कौर, सुरजीत कौर और महिला शाखा की अन्य कार्यकर्ताओं ने भी सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए।

वक्ताओं ने आंदोलन में महिलाओं की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि महिलाओं को संगठित किए बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। पितृ सत्ता के कारण महिलाओं को समाज और संगठनों में अग्रणी स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जब सरकार नीतियां बनती है तो उसमें महिलाओं के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता। केवल 9 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी मिली है और 12 प्रतिशत के पास खेती की जमीन है, जबकि वे आधी आबादी हैं।

वक्ताओं ने जोर देते हुए कहा कि महिलाएं घर और खेती दोनों काम संभालती हैं, तो वह आंदोलन भी चला सकती हैं, लेकिन इसके लिए महिलाओं को चारदीवारी से बाहर निकलना होगा। घर की चारदिवारी से बाहर निकले बिना वे समाज का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं। सम्मेलन में असफल हरित क्रांति पर भी प्रकाश डाला गया और बताया गया कि इसने महिलाओं को खेती और निर्णय लेने से कैसे बाहर कर दिया है। हरित क्रांति ने स्वास्थ्य संकट पैदा किया, जिसका महिलाओं पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। कर्ज, स्वास्थ्य संकट और आत्महत्याएं यह सभी हरित क्रांति के परिणामों की देन है। सम्मेलन में हरित क्रांति मॉडल को हटाकर प्रकृति समर्थक और टिकाऊ कृषि मॉडल बनाने की मांग की गई। साथ ही अटारी सीमा के माध्यम से भारत–पाक व्यापार खोलने, हर खेत तक नहर का पानी बिना विलंब के पहुंचाने, हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई। पंजाब के मालवा क्षेत्र में आजकल प्रत्येक घर पीने का पानी खरीद रहा है। पंजाब के पानी के मुद्दे को रिपेरियन सिद्धांत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों और मजदूरों के कर्ज को भी माफ किया जाना चाहिए।

मोगा (पंजाब) 15 जुलाई 2024

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार